फा. संख्या 6/25/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग 5,संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः सीवीडी (ओआई-03/2023)

दिनांकः 29 सितम्बर 2023

विषय: चीन जन.गण. और ताइवान में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात के संबध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 6/25/2023-डीजीटीआर - मैसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड (जिसे बाद में 'आवेदक' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 समय-समय पर संशोधित (जिसे बाद में 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान) के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमे चीन जन.गण. और ताइवान से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में जाना जाता है) से 'डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स' (इसके बाद 'विषय वस्तुओं' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या 'डीओपीपी' के रूप में संदर्भित) की सब्सिडी का आरोप लगाकर प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू करने की मांग करते हुए रियायती वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू करने की मांग की गई है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं, जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सार्वजनिक निकायों की सरकारों सहित संबंधित देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है। आवेदक ने संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों और संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं और अन्य जांच अधिकारियों के निर्धारण में

जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिपूर्ति सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला था।

ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों (एएससीएम) पर समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 25 सितंबर 2023 को चीन सरकार और ताइवान के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व दीक्षा परामर्श आयोजित किए गए थे। संबंधित देशों के प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर लिया गया है और जांच के दौरान इन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों और/या उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कथित सब्सिडी में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और धन या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है छोड़ दिया गया है या एकत्र नहीं किया गया है; पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; वगैरह।

चीन जन.गण.

I. चीन जन.गण. के संबंध में अनुदान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची।
   1. विदेश व्यापार विकास निधि अनुदान
   2. प्रसिद्ध ब्रांडों और चीन विश्व के शीर्ष ब्रांडों के विकास के लिए सब्सिडी
   3. स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति
   4. राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजना निधि
   5. निर्यात सहायता अनुदान
   6. ब्याज भुगतान सब्सिडी
   7. सुपरस्टार एंटरप्राइज़ अनुदान
   8. राष्ट्रीय उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास अनुदान एवं निधि
   9. नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष निधि
   10. जियांग्सू प्रांत का सूज़ौ औद्योगिक पार्क हरित विकास के लिए विशेष निधि
   11. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनहुइ फंड

12. जियांग्सू प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

II. चीन पीआर के संबंध में कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

13. सिनर्जिस्टिक यूटिलाइजेशन से संसाधन उत्पादों के लिए एंटरप्राइज इनकम टैक्स (ईआईटी) विशेषाधिकार
14. FIE के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र तरजीही कर नीतियां
15. प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात शुल्क और मूल्य वर्धित कर छूट
16. सहक्रियात्मक संसाधन उपयोग से उत्पन्न उत्पादों के लिए वैट में कटौती/छूट
17. उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए उद्यम आयकर ('ईआईटी') में कटौती
18. अनुसंधान और विकास व्यय की अधिमान्य पूर्व-कर कटौती
19. हाई-टेक विकास और उत्पादन के लिए हाई-टेक उद्यमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों का त्वरित मूल्यह्रास
20. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट
21. घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों पर वैट छूट
22. घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों की खरीद के लिए आयकर क्रेडिट
23. विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में टैक्स क्रेडिट
24. स्वच्छ विकास तंत्र के लिए अधिमान्य कर नीतियां
25. एसईजेड और शंघाई के पुडोंग नए क्षेत्र में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां

III.चीन जन. गण. के संबंध में पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एलटीएआर) के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची।

26. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग का अधिकार
27. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान
28. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कोयला, स्टीम कोयला और कोकिंग कोयला का प्रावधान
29. निर्यातक विक्रेता क्रेडिट कार्यक्रम
30. निर्यातक क्रेता ऋण कार्यक्रम
31. निर्यात ऋण बीमा
32. प्रमुख परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों/माननीय उद्यमों के लिए अधिमान्य ऋण
33. एसओई के लिए अधिमान्य ऋण
34. एलटीएआर पर प्राथमिक एल्युमीनियम का प्रावधान

<u>ताइवान</u>

I. ताइवान के संबंध में कर प्रोत्साहन के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

1. अनुसंधान और विकास व्यय के लिए आयकर क्रेडिट
2. इन-ज़ोन उद्यमों के लिए शुल्क और कर छूट
3. उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए शुल्क और कर छूट
4. नए उभरते, महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योगों में निवेश के लिए शेयरधारक का निवेश टैक्स क्रेडिट

II. ताइवान के संबंध में अनुदान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

5. कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान
6. अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान
7. उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय विकास निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता
9. नई उत्कृष्ट परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान
10. उत्कृष्ट प्रदर्शन चाहने वाले उद्यमों के लिए स्व-मूल्यांकन सेवा
11. पारंपरिक उद्योग प्रौद्योगिकी विकास निधि

III. ताइवान के संबंध में पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एलटीएआर) के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

12. औद्योगिक पार्कों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए सब्सिडी
13. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबंधित विषय देशों की सरकारों या सार्वजनिक निकायों सहित ऐसे संबंधित देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों का वित्तीय योगदान शामिल है और प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट और प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कुछ मामलों में ये आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/या निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर होने का भी आरोप लगाया गया है।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित है, जो जांच के दौरान संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा मौजूद और प्राप्त की जा सकती हैं।

घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

7. आवेदक ने नियमों के तहत निर्धारित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर जानकारी प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी वाले आयात के कारण हुई है।

ड जांच की शुरूआत

8. प्राधिकरण ने पाया है कि विषयगत देशों में विषय वस्तु के उत्पादन और/या निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया सबूत हैं और ऐसे सब्सिडी वाले आयात अपने मात्रा और मूल्य प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा सब्सिडी वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति के खतरे का भी आरोप लगाया गया है।

9. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण प्रतिकारी शुल्क नियमों के नियम 6 के संदर्भ में कथित सब्सिडी और परिणामी सामग्री क्षति और घरेलू उद्योग को चोट के खतरे की जांच शुरू करता है, ताकि कथित के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके। सब्सिडी देना और प्रतिकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

च. घरेलू उद्योग

10. आवेदन मेसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कथित सहायता प्राप्त की गयी विषय वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है। हालाँकि आवेदक ने अपनी दो विनिर्माण इकाइयों के नियमित रखरखाव बंद होने के कारण संबद्ध और गैर-विषय देशों दोनों से नगण्य मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि जांच अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए आयात संबद्ध वस्तुओं के उनके उत्पादन की तुलना में बहुत कम थे। चूंकि आवेदक का उत्पादन भारत में विषय वस्तु के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है, आवेदक स्थिति को पूरा करता है और प्रतिकारी शुल्क नियमों के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है

छ. विचाराधीन उत्पाद

11. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स' है।

12. पीयूसी को आमतौर पर "डिजिटल प्लेट्स" कहा जाता है। डिजिटल प्लेटों का उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में डेटा को एक छवि (डॉट पैटर्न या टेक्स्ट) के रूप में कागज पर या गैर-अवशोषक सब्सट्रेट जैसे टिन शीट या पॉली फिल्म इत्यादि पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता

है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग करके प्रिंटिंग प्रक्रिया में, डिजिटल वर्कफ़्लो एनालॉग वर्कफ़्लो के विपरीत, जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है, लेजर का उपयोग करके छवि को 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) में सीधे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।

13. डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से लेपित उच्च शुद्धता वाले लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बनाई जाती हैं। डिजिटल प्लेटें या तो सकारात्मक हो सकती हैं (गैर-उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) कार्यशील प्लेटें। प्लेट विकास प्रक्रिया में रसायनों के कम उपयोग से डिजिटल प्लेटों के प्रदर्शन में भी सुधार किया जा सकता है, जिससे यह पर्यावरण-अनुकूल बन जाता है, जिसे डिजिटल ऑफसेट "केम-फ्री" / "ग्रीन प्लेट्स" के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार, डिजिटल प्लेटों के प्रदर्शन में भी सुधार किया जा सकता है ताकि उन्हें प्रक्रिया रहित प्लेट बनाया जा सके।

14. कोटिंग घटक जिन्हें 'सेंसिटाइज़र' भी कहा जाता है विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए अलग-अलग होते हैं। कोटिंग घटकों और लेजर प्रकार के प्लेट सेटर्स के आधार पर डिजिटल प्लेटों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे थर्मल, वायलेट और सीटीसीपी/यूवी सीटीपी ('कंप्यूटर से पारंपरिक प्लेट')।

(i) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स जो इन्फ्रा-रेड ऊर्जा का उपयोग करके उजागर की जाती हैं, उन्हें थर्मल प्लेट्स कहा जाता है;

(ii) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें जो दृश्यमान और निकट-दृश्यमान प्रकाश ऊर्जा (बैंगनी लेजर) का उपयोग करके उजागर की जाती हैं, उन्हें वायलेट प्लेट कहा जाता है; और

(iii) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें जो पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके उजागर की जाती हैं, उन्हें CtCP/UV CtP प्लेट्स के रूप में जाना जाता है।

15. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी आयामों में सभी प्रकार की डिजिटल प्लेटें शामिल हैं। विषय वस्तु अधिनियम के टैरिफ उप-शीर्षक '8442.50' के अंतर्गत आती है। हालाँकि, अन्य शीर्षकों जैसे 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 और 7606.9290 के तहत भी संबद्ध वस्तुओं का आयात हुआ है। इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद की पहचान के लिए उत्पाद विवरण मान्य होगा।

16. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन

यदि कोई हो का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में दर्शाया गया है।

ज. समान वस्तु

17. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विषय वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विषय वस्तु एक समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और विषयगत देशों से आयातित डिजिटल प्लेटें आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए इन्हें नियमों के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को विषयगत देशों से आयात किए जा रहे विषय वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

18. **झ. शामिल देश**

वर्तमान प्रतिकारी शुल्क जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. और ताइवान हैं।

ञ. जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच के लिए प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक है। जांच के लिए प्रस्तावित क्षति अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।
21. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना

में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

23. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

24. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (**https://www.dgtr.gov.in/**) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी सीवीडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

27. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे सीवीडी नियम, 1995 के नियम 7(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली के नियम 8 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

30. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी, जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त की गई हो (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

32. गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और नियम 1995 के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

33. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में दर्शाए गए दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी

किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

36. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

37. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

31/7

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी